# हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2024 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला -171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

## प्रश्नकाल

## तारांकित प्रश्न

27.02.2024/1100/डीटी/एजी-1

**प्रश्न संख्याः 1239**

**उद्योग मंत्री :** सूचना एकत्रित की जा रही है।

27.02.2024/1100/डीटी/एजी-2

**प्रश्न संख्याः 1579**

**नगर एवं ग्राम योजना मंत्री :** सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

**श्री पवन कुमार काजल :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट हूं।

27.02.2024/1100/डीटी/एजी-3

**प्रश्न संख्याः 1580**

**उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) :** सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

**श्री विनोद सुल्तानपुरी :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट हूं।

अगला प्रश्न श्री एन.जी.द्वारा जारी

**27-02-2024/1105/ए.जी.-एन.जी/1**

**प्रश्न संख्या-1580 के पश्चात.....जारी**

**प्रश्न संख्या - 1581**

**श्रीमती रीना कश्यप :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि पच्छाद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पैरा पम्प चालक के 9 पद, पैरा फीटर के 4 पद

और मल्टीपर्पज़ वर्कर्स के 7 पद ही स्वीकृत किए गए हैं। यहां पर जो उत्तर दिया गया है मैं उससे बिलकुल भी संतुष्ट नहीं हूं। उत्तर में लिखा गया है कि नाहन मण्डल में 40 पद, राजगढ़ मण्डल में 20 पद, नौहराधार मण्डल में 46 पद, पांवटा साहिब मण्डल में 20 पद और शिलाई मण्डल में 56 पद भरे जाने हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि ये पद किस मापदण्ड के आधार पर भरे जाने हैं? इसके अलावा उत्तर में कहा गया है कि जल शक्ति विभाग मण्डन नाहन व मण्डल नौहराधार से 72 पदों को स्थानंतरित किया गया है, मैं पूछना चाहती हूं कि इस तरह का पक्षपात क्यों किया गया है?

**उद्योग मंत्री (प्राधिकृत)** : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्रीमती रीना कश्यप को मैं बताना चाहता हूं कि इनके चुनाव क्षेत्र में पैरा पम्प चालक के 9 पद, पैरा फीटर के 4 पद और मल्टीपर्पज़ वर्कर्स के 7 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनके क्षेत्र में जल शक्ति विभाग का मण्डल अभी कुछ समय पहले ही खुला है। इनके मण्डल में अन्य मण्डलों से पदों को स्थानांतरित किया गया है। जिसमें से नाहन मण्डल से 14 और नौहराधार मण्डल से 13 पम्प ऑप्रेटरों को शिफ्ट किया गया है। इसी प्रकार 35 मल्टी टास्क वर्कर्स भी नाहन मण्डल व नौहराधार मण्डल से शिफ्ट हुए हैं। इस प्रकार इन्हें बहुत बड़ी संख्या में पद मिले हैं। यह बात ठीक है कि जो नए पद स्वीकृत हुए हैं उसमें इन्हें कम पद मिले हैं। लेकिन अभी इनकी 29 योजनाएं आऊटसोर्स में चलाई जा रही हैं। इनके क्षेत्र में 48 पम्प ऑप्रेटर और 18 फीटर व हैल्पर पहले से मौजूद हैं। **मैं माननीय सदस्या को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अभी यह वितरण कुल 4500 लोगों का हुआ है तथा आने वाले समय में और पद भी स्वीकृत होंगे, इसलिए इनके विधान सभा क्षेत्र को ध्यान में रखकर वहां पर जितनी जरूरत होगी और वहां से जितनी मांग प्राप्त होगी, उतने पम्प ऑप्रेटर, फीटर और मल्टी टॉस्क वर्कर्स इन्हें दे देंगे।**

**27-02-2024/1105/ए.जी.-एन.जी/2**

**प्रश्न संख्या - 1582**

**श्री चंद्र शेखर** : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में अक्सर दिक्कत आ रही है कि हमारे खेल के मुख्य मैदान स्कूल अथवा कॉलेजिज़ के पास हैं और यदि वहां पर कोई खेल गतिविधियां

या कोई मेला इत्यादि का आयोजन करवाना है तो उसकी अनुमति प्राप्त करने का मामला माननीय उच्च न्यायालय तक जाता है। इसके लिए बहुत लम्बी प्रकिया से गुजरना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में खेल के मुख्य मैदानों का उपयोग सही प्रकार से हो, उसके लिए क्या युवा सेवाएं एवं खेल विभाग फण्ड उपलब्ध करवाने का प्रावधान करेगा? इसके अलावा क्या इन मैदानों को शिक्षा विभाग से बदलकर युवा सेवाएं एवं खेल विभाग को दिया जाएगा?

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री...श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

**27.02.2024/1110/केएस/एएस/1**

**प्रश्न संख्या : 1582 जारी...**

**नगर एवं ग्राम योजना मंत्री (प्राधिकृत) :** अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWPIL No. 146 of 2017 dated 11.12.2017 को एक डिसिज़न आया था कि जो शैक्षणिक संस्थानों में other than students related activities के लिए वे अलाउ नहीं करेंगे लेकिन उसमें इंटरनेशन फेयर्ज़ के लिए परमिट किया गया था। बाद में 6.11.2023 को माननीय उच्च न्यायालय ने जो इंटरनेशनल फेयर्ज़ के लिए अलाउ करने की बात की थी, उसके लिए भी मना कर दिया था। आदरणीय उच्च न्यायालय के मुताबिक इसका other than student centric activities के लिए पर्मिशन नहीं दी जा सकती लेकिन माननीय सदस्य के प्रश्न के बी भाग में जो पूछा गया है कि is there any proposal under consideration to hand over the playgrounds to YSS Department for their better upkeep and management? विभाग ने ऐसा कोई डिसिज़न नहीं लिया है कि हम YSS को देंगे लेकिन कुछेक जगह पर लगभग तीन केसिज़ में ऐसा हुआ है जहां पर YSS ने शिक्षा विभाग से इनडोर कॉम्पलैक्स बनाने की पर्मिशन मांगी थी। जो इंस्टीट्यूशन्ज़ में अगर काफी स्पेस है, वहां पर जमीन है जिसमें मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बनाया जा सकता है, वैसी तीन जगह पर यह पर्मिशन दी गई है। इसमें एक जी.एम.एस.एस.जंजैहली, जी.एस.एस.एस. माजरा और तीसरा जी.एस.एस.एस.ब्वॉयज़ नादौन है।तीन जगह पर ऐसी पर्मिशन दी गई है। तो यह मैरिट पर डिपैंड करता है कि वहां पर स्कूल में जमीन उपलब्ध है या नहीं है लेकिन जनरली यह अलाउ नहीं करते क्योंकि इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती

है, स्कूल का एकेडेमिक एन्वायरनमैंट प्रभावित होने की सम्भावना रहती है। कई बार स्कूल की प्रॉपर्टी के डैमेज होने का खतरा भी बना रहता है इसलिए जनरली इसको अलाउ नहीं करते लेकिन स्पैसिफिक केसिज़ में अगर लैंड अवेलेबल है और उस कैम्पस में फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं तो हम YSS को NOC ग्रांट करते हैं।
प्रश्न समाप्त

**प्रश्न संख्या : 1583**

**श्री के.एल. ठाकुर :** अनुपस्थित

**27.02.2024/1110/केएस/एएस/2**

**प्रश्न संख्या : 1584**

**श्री दलीप ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, मैंने विधायक प्राथमिकता में जो योजना विधायक डालते हैं, विधायक प्राथमिकता में जो डी.पी.आर. बनती है, ऐसी बहुत सी डी.पी.आर्ज़. पर अभी तक कोई कार्य नहीं हो पाया है। मैं जानना चाहूंगा कि कब तक उन पर काम शुरू होगा? दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो केंद्र से बड़ी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, उनमें कितनी धनराशि मिली है और कितनी योजनाओं का कार्य आरम्भ हो गया है ? साथ में जो हमारी डी.पी.आर्ज़ पैंडिंग हैं, वे कब तक बनेंगी? क्या विभाग द्वारा इसका कोई समय निश्चित किया गया है या नहीं?

**उद्योग मंत्री (प्राधिकृत):** अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने पूरे स्टेट की विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत लोक निर्माण व आई.पी.एच. विभाग की डी.पी.आर्ज़. की सूचना मांगी थी, उसकी सूचना इनको दे दी गई है। लोक निर्माण विभाग की कुल विधायक प्राथमिकताएं 509 प्राप्त हुई थीं और जल शक्ति विभाग की 641 प्राप्त हुई थीं। तैयार की गई डी.पी.आर्ज. में लोक निर्माण विभाग की 94 और जल शक्ति विभाग की 211 थीं। अव्यवहारिक प्राथमिकताएं लोक निर्माण विभाग में 3 और जल शक्ति में 60 थीं। इनमें से अभी तक जो सेंक्शन हुई हैं, पिछले तीन साल का ब्यौरा इन्होंने मांगा था, नाबार्ड से स्वीकृत योजनाएं लोक निर्माण विभाग में 257 हैं और जल शक्ति विभाग में 280 हैं। इनमें से लोक निर्माण विभाग की 198 योजनाएं आरम्भ कर दी गई हैं और 172 योजनाएं जल शक्ति

विभाग की आरम्भ कर दी गई हैं। नाबार्ड द्वारा लोक निर्माण विभाग में 1712 करोड़ रुपये की राशि आई है और जल शक्ति विभाग में 1502 करोड़ रुपये की राशि आई है।

**श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी** ---

**27.02.2024/1115/av/as/1**

**प्रश्न संख्या : 1584------ क्रमागत**

**उद्योग मंत्री---------- जारी**

आपने जैसे अभी कहा कि आपके चुनाव क्षेत्र की डी0पी0आर्ज0 नहीं बनी है तो मैं बताना चाहता हूं कि आपकी पिछले तीन वर्षों में नाबार्ड के अंतर्गत 96 करोड़ रुपये की 16 स्कीम्ज स्वीकृत हुई हैं। इसके अतिरिक्त आपकी नाबार्ड के अंतर्गत स्कीम शेयर इम्पोज करने की लिमिट 175 करोड़ रुपये है जिसमें से आपकी 160.63 करोड़ रुपये की पूरी हो चुकी है तथा शेष 14 करोड़ रुपये की रहती है। आपकी नाबार्ड के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग या जल शक्ति विभाग की यदि कोई स्कीम नहीं बनी होगी तो उसको विभाग कर रहा है और डी0पी0आर0 बनाने के लिए आउटसोर्स एजैंसी भी लगाई गई है। **आपके क्षेत्र की जो डी0पी0आर्ज0 नहीं बनी हैं उनको विभाग प्राथमिकता के आधार पर बनाएगा। मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में नाबार्ड के तहत लिमिट को भी बढ़ा दिया है और वह दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से लागू हो जाएगी तो उसमें आपकी बहुत सारी स्कीम्ज आ जाएंगी।**

**श्री लोकेन्दर कुमार :** अध्यक्ष महोदय, मैंने विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत जो स्कीमें दी हैं उनके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस संदर्भ में विभागों को निर्देश दें कि विधायकों द्वारा प्राथमिकता के अंतर्गत दी गई स्कीमों की डी0पी0आर्ज0 जल्दी-से-जल्दी बनाकर भेजी जाएं ताकि हमारे काम आगे बढ़े। आप बोलेंगे तो विधायक की महत्ता का भी कुछ असर होगा वरना हमारे बोलने पर तो विभाग कुछ नहीं कर रहे। इसके लिए मंत्री जी समयावधि निश्चित करें और हमें इस संदर्भ में आश्वस्त करें।

**उद्योग मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक द्वारा कही गई बात से बिल्कुल सहमत हूं। विभाग द्वारा एम0एल0ए0 प्राथमिकता की बहुत सारी डी0पी0आर्ज0 नहीं बनाई जातीं। मैं आपको **आश्वासन देना चाहूंगा कि जिस-जिस चुनाव क्षेत्र की डी0पी0आर्ज0 नहीं बनी हैं उसमें लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को आदेश दिए जाएंगे कि इनको जल्दी बनाएं क्योंकि सरकार ने इसके लिए 10 महीने का समय फिक्स किया है। अगर कोई डी0पी0आर0 फीजिबल नहीं होगी तो विधायक उस स्कीम को उसी साल सबस्टिट्यूट कर सकता है। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जिसकी भी डी0पी0आर0 नहीं बनी है वह चाहे लोक निर्माण विभाग की है या जल शक्ति विभाग की है, उसको प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाएगा।**

27.02.2024/1115/av/as/2

**प्रश्न संख्या : 1585**

**श्री केवल सिंह पठानिया :** अध्यक्ष महोदय, अखबारों में रोज़ जो दवाइयों के सेम्पल फेल होने के समाचार आ रहे हैं उसमें कमी लाने के लिए विभाग क्या कदम उठा रहा है? मैं यहां पर दिए गए विस्तृत जवाब से तो संतुष्ट हूं परंतु निकट भविष्य में दवाइयों के सेम्पल फेल न हो, उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में 8,000 से अधिक विक्रय परिसर है और 677 इकाइयां दवाइयों तथा 177 सौंदर्य प्रसाधनों का निर्माण कर रही हैं। राज्य में 39 औषधी निरीक्षक हैं जो केंद्रीय औषधी मानक नियंत्रण (सी0जी0एस0) औषधी निरीक्षकों के साथ इन विनिर्माण इकाइयों तथा विक्रय परिसर का नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इकाइयां गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रेक्टिसिस को फॉलो करें। इसके अतिरिक्त दो सूचियां एम0 और यू0 के संबंध में मानकों को ठीक तरीके से फॉलो करें। यदि कोई इकाई इस अधिनियम का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

**टी सी द्वारा जारी**

**27.02.2024/1120/टी0सी0वी0/डी0सी0-1**

**प्रश्न संख्या : 1585... क्रमागत्**

**श्री विपिन सिंह परमार :** अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सेंट्रल ड्रग स्टेंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पिछले एक वर्ष में बी0बी0एन0बी0 एरिया से कितने अर्लट लिए गए क्योंकि यहां पर प्रदेश की लगभग 35 प्रतिशत जीवन रक्षक दवाइयां बनती है और वहां दवाइयों के कितने सैंपल फेल हुए?

दूसरा, दवाइयों की गुणवत्ता जांचने के लिए क्या कोई लैब तैयार की जा रही है? मेरी जानकारी के मुताबिक निवर्तमान सरकार ने इसके लिए इनिशिएट किया था यानी आप Ultra Modern Laboratory assisted by National Institute of Pharmaceutical Education and Research क्या प्रस्तावित है? यदि प्रस्तावित है तो इसके लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है और क्या इसके लिए जमीन का चयन कर लिया गया है? बी0बी0एन0बी0 में 35 प्रतिशत से ज्यादा दवाइयां बनती है और खराब दवाइयां तैयार करने के कारण प्रदेश की छवि खराब हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्वयं भी इस विभाग को चला चुके हैं और इन्हें इसके बारे में काफी ज्यादा अनुभव भी है। पिछले एक वर्ष में बी0बी0एन0बी0 क्षेत्र में 374 दवाइयों के सैंपल फेल हो चुके हैं और जिन दवाइयों के सैंपल फेल हो चुके हैं उन कम्पनियों के नाम और उन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्योरा इस प्रश्न के जवाब में दिया गया है। जिन कम्पनियों की दवाइयों के सैंपल फेल होते हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। इनको शोकॉज नोटिस भी दिए जाते हैं और यदि आवश्यक हो तो लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं।

इन्होंने जो दूसरा प्रश्न पूछा है which is very pertinent इन्होंने पूछा है कि क्या टेस्टिंग लैबोरेटरी का निर्माण किया जा रहा है क्योंकि इसके लिए हमें कण्डाघाट या अधिकृत लैबोरेटरी चण्डीगढ़ पर निर्भर रहना पड़ता है? The best thing is, the work of this laboratory started when the Hon'ble Member Shri Vipin Singh Parmar was Health and Family Welfare Minister himself in the last Government. **वह**

**लैबोरेटरी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और शीघ्र ही इसका लोकार्पण कर दिया जाएगा।**

**27.02.2024/1120/टी0सी0वी0/डी0सी0-2**

यह 32 करोड़ रुपये की लागत से बनी है और इसके होने से दवाइयों की गुणवत्ता जांचने का सशक्त साधन उपलब्ध हो जाएगा और प्रदेश की जनता को सही दवाइयां मिलेगी। मुख्य मंत्री महोदय इस बारे में हमेशा कार्यरत रहते हैं और उनके निर्देशानुसार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इस तरह की घटना होती है we will look after it and we are doing our best.

**डॉ0 जनक राज** : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन सैंपल को जांच करने और रिपोर्ट करने की जो व्यवस्था है उसके अनुसार जब दवाइयां मार्केट में आ जाती हैं और लोग उनको खा चुके होते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि उन दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। इसमें सुधार किया जाना आवश्यक है।

एन0एस0 द्वारा .. जारी

27-02-2024/1125/एन0एस0-डी0सी0/1

प्रश्न संख्या : 1585 ------क्रमागत

डॉ0 जनक राज -------जारी

क्या सरकार नियमों में बदलाव करने का विचार रखती है? दूसरा, ड्रग कंट्रोलर का पद कई दिनों से रिक्त पड़ा है और उसको सरकार भर नहीं रही है। इस पद को कब तक भर दिया जाएगा?

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और अब विधायक बन गए हैं। मैं कभी-कभी सोचता हूं कि दवाइयों के अलावा लोगों को इस क्षेत्र में और सुविधाएं तथा उनकी तकलीफों के और प्रश्न आएं तो हमें अच्छा

लगेगा। Anyway he is asking very pertinent question. Hon'ble Speaker Sir, there are stages of manufacturing medicines एक प्री-मैन्यूफेक्चरिंग स्टेज और दूसरी पोस्ट-मैन्यूफेक्चरिंग स्टेज । ये दोनों स्टेजिज ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एम0ओ0यू0 का ध्यान रखा जाए, इन मानकों को ठीक किया जाए। तीन चीजें जरूरी होती हैं humidity, temperature and light and these three things are repeatedly taken care during manufacturing and storage. When they are sent to another areas वहां पर अगर इन तीन चीजों में फर्क हो तो कभी-कभी गुणवत्ता में फर्क आ जाता है। इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। दूसरा, आपने यहां पर ड्रग कंट्रोलर के बारे में कहा है। The earlier Drug Controller has retired and the second Drug Controller in the chain has been given the responsibility. I am sure he will do his job properly.

**डॉ0 जनक राज :** अध्यक्ष महोदय, जितना नॉलेज मुझे है तो मैं बताना चाहूंगा कि एक कंपनी जिस नाम से है अगर उसका सैंपल फेल होता है तो उसको बंद कर दिया जाता है या एक्शन लिया जाता है। वही व्यक्ति अगले दिन नये नाम से कंपनी बना लेता है। जो सिस्टम के लूपहोल्ज हैं जिनका फायदा कुछ लोग उठाते हैं और प्रदेश की जनता और देश की जनता के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसको रोकने के लिए सरकार की क्या योजना है?

27-02-2024/1125/एन0एस0-डी0सी0/2

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अनुभव के आधार पर यह बात कही है। यह बात ठीक है कि सचमुच में ऐसा धोखा हो सकता है कि वहां से कंपनी बंद की और किसी और नाम से चला दी। मैं यह कह सकता हूं कि हमारी एजैंसीज are very active in looking after the law-abiding aspect and **I assure you if someone does such a thing and we find anyone doing wrong, second time he will not only be told to close his manufacturing unit but also leave the State of**

**Himachal Pradesh.** We are very strict on this issue and I have already taken a conference on this.

**श्री विपिन सिंह परमार** : अध्यक्ष महोदय, लगभग 600 से अधिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज बी0बी0एन0 के इलाके में दवाइयां बनाती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार को इससे कुल कितना लाभ या रेवेन्यू प्राप्त होता है? आप इसकी सटीक जानकारी दें। दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों यहां नकली दवाइयां बनाने का काम किया जा रहा था और उन दवाइयों का जखीरा अन्य प्रदेशों में पकड़ा गया। उन दवाइयों को कुछ डॉक्टरों ने लिखा और मरीजों ने ले भी लिया था। मंत्री जी ने तो कह दिया कि हमने उनको नोटिस जारी किया है और कुछ महीनों के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ कंपनीज ब्लैक लिस्टिड की गई हैं? यहां पर डॉ0 जनक राज जी भी हवाला दे रहे हैं तो क्या ऐसे शातिर फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मालिकों को आइडेंटिफाइ करेंगे जो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और इन्होंने आपकी चेयर को सुशोभित किया है तथा सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी रहे हैं। मेरा ज्ञान इनसे ज्यादा तो नहीं हो सकता। फिर भी I can assure you about revenue, the exact detail I will give you in writing definitely how much revenue actually we are getting. Secondly you have asked pertinent question regarding.

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

27.02.2024/1130/RKS/HK-1

प्रश्न संख्याः 1585... जारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री... जारी

I can assure you about revenue exact detail I will give you in writing definitely how much revenue actually we are getting. नम्बर दो जो आपने नशे के ऊपर पर्टिकुलर प्रश्न पूछा है, नशे का कारोबार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चला हुआ है और इसकी हमें सबसे ज्यादा फिक्र है। To tell you the truth, I have personally brief the Superintendent of Police of this knowing his capability as he is just changed these days. Really speaking, there is a need to pin down such people and to nab them also. इसके प्रचलन से हमारे कल के भविष्य का क्या होगा? हमारी न्यू जनरेशन किस प्रकार की होगी? हम देखते हैं कि suddenly there was two deaths in Solan and they just took 24 hours and they just took a very small quantity of Chitta. इस खेल में हमारी बड़ी पैनी नजर है। मैं माननीय सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि मैं इसकी रोकथाम के लिए पर्सनली इंवोल्वड हूं और जो इस प्रकार का काम करने के लिए संलिप्त हैं उन्हें नजर में रखा जाएगा।

27.02.2024/1130/RKS/HK-2

**प्रश्न संख्याः 1586**

**श्री सुख राम चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, रिवेंप्ड डिस्ट्रिब्यूशन सैक्टर स्कीम के तहत केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को 3700.69 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के तहत आर.डी.एस.एस. स्मार्ट मीटरिंग वर्क्स कंपोनेंट में 1788.49 करोड़ रुपये और आर.डी.एस.एस. लॉस रिडक्शन कंपोनेंट में 1912.20 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। आर.डी.एस.एस. के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग वर्क्स के लिए निविदाएं अगस्त, 2022 तथा अक्तूबर, 2022 में आमंत्रित की गई थीं। जब मुख्य मंत्री जी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो 6 महीने बाद टेंडर लगे थे उन्हें रद्द कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि जब अक्तूबर, 2022 में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं तो उस समय किन-किन फर्मों ने टेंडर भरे थे, उस टेंडर को रद्द करने का क्या कारण रहा और अभी तक यह टेंडर क्यों नहीं किया गया? मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि जो वर्ष 2022 व वर्ष 2023 में टेंडर भरे गए थे उसमें क्या रेट में एनहांस हुआ है या फिर यह माइनस में गया है?

**उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) :** अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री थे उस वक्त इस योजना की शुरूआत की गई थी। उस वक्त इसके कंपोनेंट के टेंडर हुए थे। लेकिन जिन कंपनियों ने टेंडर्ज में भाग लिया वे इसके नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पाई जिस कारण इस टेंडर को रद्द करना पड़ा। उसके बाद तीसरी बार निविदाएं दिनांक 10.04.2023 को आमंत्रित की गई जिनका तकनीकी तथा वाणिज्यिक मूल्यांकन करने के पश्चात् मामला हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के निदेशक मंडल के अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है जिसे जल्द अवार्ड कर दिया जाएगा। जैसे आपने कहा कि यह कार्य दो फेस में किया जाना है। पहले फेस में स्मार्ट मीटरिंग वर्क्स और दूसरे में लॉस रिडक्श का कार्य होगा। लॉस रिडक्शन कंपानेंट में अगस्त, 2022 में टेंडर हुए थे जिसे दिनांक 17.02.2023 को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद मई, 2023 में दोबारा टेंडर किए गए जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटिड के पास विचाराधीन हैं। इन टेंडरों को जल्द अवार्ड कर दिया जाएगा ताकि काम शुरू किया जा सके। यह टेंडर किन कंपनियों को आबंटित किए थे इसकी मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको यह जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा।

अगला प्रश्न श्री बी.एस.द्वारा जारी

27.02.2024/1135/बी.एस./एच के/-1

**प्रश्न संख्याः 1587**

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य प्रकाश राणा जी, सूचना एकत्रित की जा रही है। PWD Minister is not here, he is a proxy Minister who is replying.

**श्री प्रकाश राणा :** अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न है, यह मेरी विधान सभा चुनाव क्षेत्र से संबंधित है। यहां पर हमारे 85 किलोमीटर रोड को कंपनी द्वारा खोद दिया गया है। जिस कंपनी ने 5-जी केबल बिछाना था उसके द्वारा यह कार्य हो रहा था और मैंने दिनांक 19.12.2023 को सदन में एक प्रश्न भी लगाया था कि कितने किलोमीटर रोड को खोदा गया है और कितना पैसा कंपनी ने विभाग को दिया है। इसका जो उत्तर आया उसमें कहा गया है कि कंपनी द्वारा विभाग को तकरीबन 84.66 किलोमीटर रोड खोदा गया है और उसके लिए 9,56,80,401 पैसा कंपनी द्वारा विभाग को दिया गया। उसमें मैंने यह भी पूछा

था कि यह काम कितना पूरा हुआ है और कितना बाकी है? इसके जवाब में लिखा गया कि जो कंपनी ने काम किया है वह तकरीबन 77.805 किलोमीटर पूरा कर लिया गया है और इसके लिए विभाग ने 1,80,56,229 रुपये खर्च किए और बाकी सात करोड़ रुपये के करीब बाकी पैसा बचा हुआ। जब इस सत्र में 22 तारीख को जो मैंने प्रश्न पूछा था, उसमें यह जवाब आया कि यह जो पैसा है यह सारे-का-सारे खर्च कर दिया गया है, केवल मात्र 77 लाख रुपये की इसमें बचा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहात हूं कि ये डेढ़ महीने में सात करोड़ रुपया कैसे खर्च हो गया? जब रोड में केबल बिछाई गई तो रोड की पूरी नालियों को खोद दिया गया और जब ये खोदी गई तो इनकी चौड़ाई तीन फुट और गहराई तकरीबन चार फुट की थी। इससे हमारे सारे रोड्ज बह गए। मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो ड्रेनेज सड़कों के खोदे थे उन्हें कितना बनाया? यदि कहीं एक किलोमीटर ही बनाया है तो हमें बताने की कृपा करें। यह बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसकी जांच करवायें? जो सात करोड़ रुपये बताया गया था वह पैसा कहां चला गया?

**उद्योग मंत्री, अधिकृत :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सूचना मांगी थी वह टैंडर से संबंधित है और जो सूचना अभी मांगी गई है **यह प्रश्न का भाग नहीं है। जो सूचना माननीय सदस्य ने अभी मांगी है उसकी जानकारी दे दी जाएगी।** अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई **अनियमितताएं होंगी या पैसे की कमी होगी तो उसे ठीक किया जाएगा और एक्शन भी ले लिया जाएगा।** अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है और यह पोस्टपोन प्रश्न किया गया है it does not pertain to this question.

27.02.2024/1135/बी.एस./एच के/-2

**प्रश्न संख्याः 1588**

**श्री रवि ठाकुर :** उपस्थित नहीं।

**प्रश्न संख्याः 1589**

**श्री सुधीर शर्मा :** उपस्थित नहीं

**प्रश्न संख्याः 1590**

**श्री होशियार सिंह :** उपस्थित नहीं

**श्री लोकेन्दर कुमार :** अध्यक्ष महोदय, जो मुझे प्रश्न का उत्तर मिला है इसमें जिस तरह से नियमों का हवाला दिया गया है कि 10 वर्ष की नियमित सेवाएं होनी चाहिए। परंतु मैं तो यह जानना चाहता हूं कि सरकार बार-बार यह कह रही है कि हमने कर्मचारियों को पुरानी पैंशन दी है। परंतु प्रदेश के अन्दर हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो इस समय ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या जिन लोगों की नौकरी अनुबंध के आधार पर 10 वर्ष तक पूरी हुई है उन्हें भी पैंशन दी जाएगी? सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन की बात की है। मैं समझता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन का मतलब यह है कि यह जो व्यवस्था है इस पर अमूल-चूल परिवर्तन होने चाहिए। जो नियम प्रश्न के उत्तर में भेजे हैं, मैं चाहता हूं कि क्या सरकार इन नियमों में परिवर्तन करेगी? ताकि जिन-जिन लोगों ने सरकारी नौकरी की, चाहे वह 10 वर्ष की है या वह पांच वर्ष की है, क्योंकि उन सभी ने सरकार के कार्य में कुछ-न-कुछ श्रम दिया है, उन सबको सरकार पैंशन देने का विचार रखती है?

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

27.02.2024/1140/डीटी/एजी-1

प्रश्न संख्या 1590 जारी..

**उद्योग मंत्री (प्राधिकृत):** अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसका जवाब दिया गया है। जो कांट्रेक्ट की नौकरी है उसे पेंशन लाभ के साथ नहीं जोड़ा जाता। पहले अनुबंध की अवधि आठ वर्ष थी फिर उसे घटा कर छः साल किया गया, फिर पांच साल किया गया और उसके बाद तीन साल किया गया, फिर 2 वर्ष किया गया। पेंशन देने के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें केवल नियमित सेवाओं के वर्षों को ही गिना जाता है। इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहूंगा कि नियमित सेवाओं में भी कर्मी को 10 साल का न्यूनतम सेवाकाल पूर्ण करना होता है उसी के बाद वह पेंशन का अधिकारी हो सकता है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अभी ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त जो माननीय सदस्य ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना के लगभग 3899 लोगों को ए0जी0 ऑफिस द्वारा पेंशन के लिए प्राधिकृत किया

जा चुका है। जो यह पुरानी पेंशन है उसमें 3899 लोगों को पुरानी पेंशन स्कीम में रजिस्ट्रड करके उनको पुरानी पेंशन में ले लिया गया है।

**श्री लोकेन्दर कुमार :** अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी पूछा है कि सरकार व्यवस्था परिवर्तन की बात बार-बार कर रही है। प्रदेश में हज़ारों कर्मचारी हैं जो पेंशन के दायरे में आते हैं लेकिन इनको पेंशन नहीं मिल रही है इसलिए वह आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है, वह उन्हें भी पेंशन देगी। क्या सरकार भविष्य में नियमों को चैंज करने का विचार रखती है कि इन नियमों को बदला जायेगा? ताकि आने वाले समय में इन लोगों को पेंशन मिल सके। उन लोगों से पैसे भी जमा करवा लिये गये हैं।

**उद्योग मंत्री (प्राधिकृत):** अभी सरकार ऐसा विचार नहीं रखती है। अभी जो नियम है उनके अनुसार 10 साल की रेग्यूलर सर्विस चाहिए।

**डॉ0 जनक राज :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा की बार -बार सरकार ने जो अपनी कांट्रेक्ट नीति में चेंज किया उसका क्या कारण है। पहले इस नीति के अंतर्गत 8 साल के बाद रेगुलर किए जाने का प्रावधान था, फिर इसे घटाकर 4 साल किया गया बाद में फिर इसे 2 साल कर दिया गया।

27.02.2024/1140/डीटी/एजी-2

इसमें उन लोगों का क्या कसूर जिन्होंने आठ साल या चार साल संविदा में नौकरी की। जो विसंगति पैदा हुई है और जो कर्मचारी इस कारण प्रभावित हुए हैं क्या उन कर्मचारियों की इस समस्या के लिए सरकार कोई विचार रखती है या नहीं?

**उद्योग मंत्री (प्राधिकृत):** माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कह दिया है कि अभी सरकार विचार नहीं रखती है। इसके लिए 10 साल की नियमित सेवा अवधि होनी ही चाहिए तभी कर्मचारी पेंशन का अधिकारी होगा।

**प्रश्न संख्या 1591**

श्री त्रिलोक जम्वाल अनुपस्थित

27.02.2024/1140/डीटी/एजी-3

**प्रश्न संख्या 1592**

**डॉ0 हंस राजः** अध्यक्ष महोदय, जो सूचना दी गई है इसमें समस्या ये है कि सरकार ने खुद ही माना हुआ है कि हम हर साल एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। जब अधीनस्थ चयन कमीशन, हमीरपुर को रद्द किया गया तो इन्होंने ये दलील दी कि ये चयन बोर्ड इसलिए रद्द किया गया है कि इसमें धांधलियां हुईं हैं। ये बात ठीक है कि धांधलियां हुईं हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिन्होंने धांधलियां की थी उनको तो जेल में डालों, कोई भी सजा दो, कोई दिक्कत नहीं हैं। लेकिन उसके बाद भी आपने अधीनस्थ चयन कमीशन पुर्नगठित नहीं किया है इस बात को सरकार ने भी खुद माना है। मेरा इसके साथ एक प्रश्न ये है कि क्या आप उस तरह की व्यवस्था जो पूर्व में थी वैसी करेंगे? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी और जिस तरह से जे0बी0टी0 के अभ्यर्थी अभी वेटिंग में हैं, शास्त्री पद के अभ्यर्थी अभी वेटिंग में हैं और अन्य विभागों में भी बहुत सारे पद भरे जाने हैं आप कब तक ये प्रक्रिया शुरू कर देंगे?

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

**27-02-2024/1145/वाई.के.-एन.जी/1**

**प्रश्न संख्या-1592.....जारी**

**डॉ0 हंस राज के पश्चात.....जारी**

**उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) :** अध्यक्ष महोदय, उत्तर में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग करके इसके स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को स्थापित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर में बहुत

सारी अनियमितताएं सामने आई थी, जैसे पेपर लीक होना या उसे बेचना और वहां के कर्मचारियों की संलिप्तता पाया जाना। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों को पेपर बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। इन सब घटनाओं के बाद मुख्य मंत्री जी ने पुराने आयोग को भंग करके एक नया चयन आयोग स्थापित किया है ताकि हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार व पेपर बिकने की घटनाएं न हों। इस नए आयोग में जल्दी ही साक्षात्कार लेने का कार्य शुरू किया जाएगा। माननीय सदस्य ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की पेंडिंग भर्तियों के संदर्भ में पूछा है तो मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि इन पेंडिंग भर्तियों के लिए सरकार ने श्री मुकेश अग्निहोत्री, उप-मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक सब-कमेटी गठित की है। **जिन भर्तियों में पेपर्स नहीं बिके होंगे या कोई अन्य धांधलियां नहीं हुई होंगी तो उनके परिणाम शीघ्र घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उन पर सरकार गम्भीर है और उन्हें भी जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि क्लास-3 की नौकरियों की प्रक्रिया को भी जल्दी आरम्भ कर दिया जाएगा** ताकि प्रदेश के बच्चों को रोज़गार मिल सके।

**डॉ0 हंस राज :** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आश्वस्त तो करवा रहे हैं। लेकिन हमारा व प्रदेश के युवाओं का कहना है कि सरकार ने नया आयोग गठित तो कर दिया है लेकिन वह सही प्रकार से एक्टिव नहीं है। दूसरा विषय यह है कि वर्तमान सरकार हर बार कमेटियां गठित तो कर देती हैं लेकिन 14 माह बीत चुके हैं



उनका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। प्रदेश के युवा जे.ओ.ए. (आई.टी.) को लेकर आज भी धरने पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा शास्त्री के अभ्यार्थी भी धरने पर बैठे हुए हैं। जे.बी.टी. के लोग भी इंतेज़ार में बैठे हुए हैं। आज हमारे सभी स्कूल्ज़ खाली हो चुके हैं। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि ये कमेटियां गठित करना तो ठीक है लेकिन उस नए आयोग को

गम्भीरतापूर्वक सक्रिय कर दीजिए। इसके अलावा प्रदेश के युवाओं के साथ आपने प्रोमिस किया हुआ है और उसे पूरा करने के लिए नए आयोग के माध्यम से भर्तियां शुरू कर दीजिए। मैं कहना चाहता हुं कि मंत्री जी क्या इस माननीय सदन को आश्वस्त करेंगे कि इस संदर्भ में उचित कदम उठाए जाएंगे?

**उद्योग मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर विषय है और हम माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हैं। यह विषय हिमाचल प्रदेश के नौजवानों से संबंधित है। जे.ओ.ए. (आई.टी.)-817 में लगभग 1800 पदों पर भर्तियां होनी हैं और सरकार इसके परिणाम को जारी करने के लिए गम्भीर है। इसकी लड़ाई हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ी है। वहां से जब यह मामला सरकार के पास आया तो उसमें बहुत सारी लीगल उलझनें पाई गई हैं। जिन लोगों ने पेपर खरीदे हैं वे लोग पकड़े जा चुके हैं जिस कारण लॉ विभाग उसमें कुछ ओपीनियन दे रहा है। जिस कारण कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जितनी भी भर्तियां रूकी हुई हैं और जिनमें कोई भी अनियमितताएं नहीं हैं उनके परिणाम निकालने के लिए कैबिनेट सब कमेटी गठित कर दी जाए। सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में जो भी परिणाम घोषित किए जाएं उसमें दोबारा से लीगल उलझनें पैदा न हों। ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति माननीय कोर्ट में चला जाए और स्टे ले ले तथा वे सारी भर्तियां एक बार फिर से रूक जाएं। इन सभी पहलुओं को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि इस प्रकार कार्य किया जाए जिससे भविष्य में लीगल उलझनें न हों। जो भर्तियां रूकी हुई हैं उनमें हम क्या-क्या कर सकते हैं और उन पर लीगल एंगल से भी विचार किया जा रहा है। कैबिनेट जो भी फैसला करेगी वह सोच-समझ कर ही करेगी और हिमाचल प्रदेश के युवाओं के हितों की रक्षा करेगी।

अगला प्रश्न .....श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

**27.02.2024/1150/केएस/एजी/1**

**प्रश्न संख्या : 1593**

**श्री विनोद कुमार :** अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था, उसके उत्तर में कहा गया है कि गत वर्ष बरसात के कारण 3919 व्यक्तियों के घर के आगे भूस्खलन हुए इनमें से 3919 वे लोग हैं जिनके घर के आगे मनरेगा के तहत डंगे लगे हुए हैं। दूसरा, इन्होंने यह भी कहा कि 1829 लोगों के घरों के आगे डंगे लगा दिए गए हैं। मेरा सिर्फ इतना निवेदन हे कि 2090 लोग बचते हैं, क्योंकि अभी तक सरकार की ओर से डंगों के लिए मनरेगा के अंतर्गत 1 लाख रुपये दिए जा रहे हैं लेकिन साथ में यह भी कहा जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष के बाद इस राशि को 50 हजार रुपये किया जाएगा। मेरा माननीय मंत्री जी से और यहां पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी भी बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि नाचन ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के जिनके भी घरों के आगे स्लाइडिंग हुई है और जिनको इस बरसात के चलते आपने 1 लाख रुपये की राशि देने की जो बात की थी, मैं चाहूंगा कि सभी पात्र लोगों को 1 लाख रुपये की राशि मिले, 50 हजार रुपये ना मिले, यह मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है।

**कृषि मंत्री (प्राधिकृत) :** अध्यक्ष महोदय, पिछली बरसात में माननीय विधायक श्री विनोद कुमार जी के विधान सभा क्षेत्र में 3919 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं जिनके डंगे गिरे हैं। इसमें से 1829 आवेदकों के डंगे लगाए जा चुके हैं तथा शेष 2090 रह गए हैं। जो 3919 डंगे लगाए गए हैं, ये मनरेगा के तहत लगाए गए हैं। इसके लिए कोई स्पैशल ग्रांट नहीं थी। **जो बाकी बचे हैं उनको भी चरणबद्ध तरीके से मनरेगा के तहत ही लगाया जाएगा।** अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो 1 लाख रुपये की बात की, यह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी का प्रश्न है। अगर आप इनसे अलग से प्रश्न पूछेंगे तो ये उसका जवाब देंगे।

**श्री विनोद कुमार :** अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी भी यहीं पर बैठे हैं। मेरा यही निवेदन रहेगा कि 2090 जो पात्र लोग बचे हैं, इनको भी डंगों के लिए 1 लाख रुपये की ही राशि दी जाए, यह मेरा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी से निवेदन है।

**अध्यक्ष :** माननीय मंत्री जी, क्या आप इस प्रश्न का अभी जवाब देंगे?

27.02.2024/1150/केएस/एजी/2

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 1 लाख रुपये प्रति जॉब कार्ड के हिसाब से जो नोटिफिकेशन 12 जुलाई को की गई थी, उसमें सभी को मिले हैं लेकिन आपकी नज़र में अगर कोई छूट गया है, तो उसके बारे में सम्बन्धित बी.डी.ओ. को आवेदन दें, आप भी मुझे व्यक्तिगत रूप से बताएं, यह मैं पूरे हाउस के माननीय सदस्यों के लिए कह रहा हूं कि अगर कोई छूट गया है तो बी.डी.ओज़ को आवेदन दें। वे सम्बन्धित डी.सी. को फारवर्ड करेंगे और हम लोग तुरंत सेंक्शन करवा देंगे। वे ex post facto होंगे।

दूसरा, आपने कहा कि 1 लाख रुपये दिए हैं, तो वे पूर्ण रूप से लगे हैं। मनरेगा एक एक्ट है, कोई स्कीम नहीं है। एक्ट के हिसाब से ही काम होना है। कइयों के कार्य दिवस पूरे हुए हैं इस वजह से वह काम पिछले वित्तीय वर्ष में नहीं कर पाए। अगले वित्तीय वर्ष में, 31 मार्च के बाद कवर हो जाएंगे। एक लाख रुपये तो सभी को सेंक्शन हुए ही हैं।

प्रश्न समाप्त

**अगला प्रश्न श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी** ---

27.02.2024/1155/av/ag/1

**प्रश्न संख्या : 1594**

**श्री सुरेन्द्र शौरी :** अध्यक्ष महोदय, बंजार एक बहुत ही दुर्गम विधान सभा क्षेत्र है और वहां लो वोल्टेज की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। पिछली सरकार ने गुशैनी अनुभाग को दो भागों में बांटकर बठाड़ में एक नया जे0ई0 सैक्शन खोला था परंतु उसको रद्द किया गया है। क्या मंत्री जी उसको दोबारा से खोलने बारे आश्वस्त करेंगे क्योंकि हमारे वहां पर बिजली की बहुत ज्यादा दिक्कत है और वहां पर दूसरा स्टाफ भी नहीं है। हमारा 33के0वी0 का एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब-स्टेशन कुल्लू-भून्तर के पास बजौरा में स्थापित है जिसके कारण दूरदराज के क्षेत्रों में बिजली की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। मैं माननीय

मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार भविष्य में लारजी और बंजार के बीच में 132 के0वी0 का एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब-स्टेशन स्थापित करने का विचार रखती है?

**उद्योग मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जैसे कहा कि इनका सैक्शन बहुत बड़ा है परंतु अभी फिलहाल गुशैनी को दोबारा शुरू करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। इसके अतिरिक्त अभी थलौट मण्डल के अंतर्गत थलौट से सिधवां 33 के0वी0 सब-स्टेशन तक डबल सर्किट लाइन बिछाने का भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। **परंतु विद्युत मण्डल थलौट के अंतर्गत प्रस्तावित 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन गुशैनी तक सिंगल सर्किट लाइन बिछाने का प्रावधान रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत लिया गया है जिससे बंजार को 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। उससे आपकी लो वोल्टेज का काफी हद तक समाधान हो जाएगा।**

**समाप्त**

**प्रश्न संख्या : 1595**

**(अनुपस्थित)**

**प्रश्न संख्या : 1596**

**(अनुपस्थित)**

**27.02.2024/1155/av/ag/2**

**प्रश्न संख्या : 1597**

**श्री मलेन्द्र राजन :** अध्यक्ष महोदय, हर पंचायत में जो नये पंचायत घर बन रहे हैं उनको जैसे कि मिनी सचिवालय की तरह बनाया जा रहा है और वहां पर पंचायत स्तर के सभी कार्यालय एक ही भवन के अंदर होंगे। उसके लिए सरकार ने 1.15 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में इन भवनों को सोलर सिस्टम के तहत लाया जाएगा?

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में मैं यह बताना चाहूंगा कि अभी इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत हमारे पास कोई बजट प्रोविजन नहीं है। प्रदेश में वर्तमान में 3615 ग्राम पंचायतें और 88 ब्लॉक्स हैं और इनको सोलेराईज करने में काफी खर्चा आएगा। अगर कभी भविष्य में इसके लिए फण्ड का प्रावधान होगा तो इनको सोलर सिस्टम से जोड़ा जाएगा। वैसे तो माननीय विधायक द्वारा मांगी गई सूचना के अंतर्गत विस्तृत जवाब दे दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत घोषणा की है कि वे चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी बिल्डिंग्ज में रूफ टोप व सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। हमें इसमें ग्रीन एनर्जी का लाभ मिलेगा तो **मैं खुद भी चाहूंगा कि सारी पंचायतें सोलेराईज हों। हम भी एक प्रोजैक्ट तैयार करके उसकी डी0पी0आर0 केंद्र सरकार को भेजेंगे ताकि हमें वहां से भी कुछ फंडिंग प्राप्त हो सके।**

**प्रश्न काल समाप्त**

**श्री विनोद कुमार नियम- 62 के तहत टी सी द्वारा जारी**

**27.02.2024/1200/टी0सी0वी0/ए0एस0-1**

**व्यवस्था का प्रश्न**

**अध्यक्षः** माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी आप क्या कहना चाहते है?

**श्री विनोद कुमार :** अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम-62 के तहत भी ब्लूम्ज बी0एड कॉलेज का एक महत्वपूर्ण इश्यू उठाया है। मैं माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि दिनांक 07.12-2023 को बी0एड की काउंसलिंग हुई थी और वह काउंसलिंग एस0पी0यू0 की ओर से करवाई गई थी। उसके बाद मैरिट के आधार पर छात्रों को कॉलेज दिए गए। 95 ऐसे छात्र हैं जिनको ब्लूम्ज कॉलेज में भेजा गया और वहां पर उनकी क्लासिज भी सुचारु रूप से शुरू हो गई और उसके बाद फर्स्ट समैस्टर के एग्जाम की तिथियां निर्धारित की गई। लेकिन इन बच्चों के रोल नम्बर नहीं आए और इन बच्चों ने कई बार इस बारे में ब्लूम्ज

कॉलेज के प्रधानायार्य या एम0डी0 से बात की। उसके बाद वे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी भी गए और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला भी आए। उन्होंने इसके बारे में मंत्री जी से भी बात की। ...(व्यवधान)

**संसदीय कार्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर डिस्कशन हो चुकी है या फिर ये इसको अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान भी रख सकते हैं क्योंकि यहां इसका उत्तर नहीं आएगा। ...(व्यवधान)

**Speaker** : I have allowed you under Point of Order. You should be very specific towards the issue and whatever comes under Rule-62, that is under consideration of this Secretariat. So you should be very specific towards the issue.

**श्री विनोद कुमार** : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में 95 बच्चे मंत्री जी से भी मिले हैं। इन बच्चों के एग्जाम 5 मार्च से शुरू होने वाले हैं। इसके बारे में जब पता किया गया तो पता चला कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी और ब्लूम्ज कॉलेज के बीच में कुछ इश्यूज चले हुए हैं जिसके कारण से बच्चों को रोल नम्बर नहीं दिए जा रहे हैं। मेरा मंत्री जी आग्रह है कि उन बच्चों को रोल नम्बर इश्यू किए जाएं और यदि यूनिवर्सिटी और ब्लूम कॉलेज के बीच में कोई इश्यू है तो उनको किसी और कॉलेज में शिफ्ट किया जाए ताकि उन बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हों क्योंकि ये बच्चे परेशान है और इनके पेरेंट्स हमें हररोज फोन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इसको गम्भीरता से लें।

**27.02.2024/1200/टी0सी0वी0/ए0एस0-2**

**Speaker** : Whether the Government will look into this further, Hon'ble Parliamentary Affairs Minister?

**Parliamentary Affairs Minister** : Hon'ble Speaker, Sir, the Hon'ble Member Shri Vinod Kumar, has raised the issue. The Government has taken note of it और **जो भी करना पॉसिबल होगा, सरकार वह करने का प्रयास करेगी।**

**27.02.2024/1200/टी0सी0वी0/ए0एस0-3**

**कागज़ात सभा पटल पर**

**अध्यक्ष :** अब उद्योग मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

**उद्योग मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं -

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, अधीक्षक ग्रेड-1 (ग्रुप-ए), भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन), 2024 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-ए(ए)3-3/2023, दिनांक 12.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.02.2024 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, निजी सचिव, ग्रुप-ए (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम (प्रथम संशोधन), 2024 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-ए(ए)3-7/2023, दिनांक 09.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.02.2024 को प्रकाशित।

**अध्यक्ष :** अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थानों के लेखाओं का वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23, की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

**27.02.2024/1200/टी0सी0वी0/ए0एस0-4**

## <u>विधायी कार्य</u>

## सरकारी विधेयकों की पुरः स्थापना

**अध्यक्ष** : अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि बाल-विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**एन0एस0 द्वारा ... जारी**

27-02-2024/1205/एन0एस0-ए0एस0/1

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि बाल-विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि बाल-विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि बाल-विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

**प्रस्ताव स्वीकार**
**अनुमति दी गई।**

अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बाल-विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करेंगे।

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बाल-विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करता हूं।

**अध्यक्ष :** बाल-विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 4) पुरःस्थापित हुआ।

27-02-2024/1205/एन0एस0-ए0एस0/2

## वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए बजट अनुमान

अब वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा होगी। पिछले कल मांग संख्या : 9, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित चर्चा हो रही थी और उसमें जो कटौती प्रस्ताव आए थे तो उन पर लगभग चर्चा पूरी हो चुकी है लेकिन माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी का वक्तव्य 5-6 मिनट का हो गया था और अब आप अपना वक्तव्य 5 मिनट में समाप्त करें। उसके बाद माननीय सदस्य श्री दीप राज जी चर्चा में भाग लेंगे और उसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे। जो माननीय सदस्य कल उपस्थित नहीं थे उनको इजाजत नहीं दी जा सकती।

**श्री इन्द्र सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले कल मांग संख्या : 9, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर बोल रहा था और मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी आपत्तियां हैं उनके बारे में बोलने के लिए आपने समय दिया था। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र की एक बेटी कुमारी स्वन्या पुत्री श्री हेम राज निवासी चराण खाबू के साथ 10 तारीख को रेप हुआ और रेप होने के बाद जो लाइव टैस्ट होना था। चराण खाबू के साथ रिवालसर अस्पताल है और वहां पर डॉक्टर न होने के कारण उसको राजनीतिक संरक्षण देते हुए आगे रैफर कर दिया गया। रैफर करने के बाद वहां पर भी उसका समयबद्ध तरीके से टैस्ट नहीं हुआ। जिसके कारण आरोपियों को आज दिन तक पकड़ा नहीं गया। मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या रिवालसर अस्पताल में यह टैस्ट होता है? यह लड़की ग्याहरवीं कक्षा में पड़ती है। ये लड़की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, चौकीगाण में पढ़ती थी। जब ये लड़की स्कूल आ रही थी तो बीच रास्ते से ही इसको उठा लिया गया। अगर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नियमों की पालना न की जाए और डॉक्टर के द्वारा टैस्ट करने से मना कर दिया जाए तथा उसको डीले किया जाए तो यह अच्छी बात नहीं है। यह बात चाहे डॉक्टरों या प्रयोगशाला के प्रति है तो यह अच्छी बात नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि जब इस तरह की वारदातें

होती हैं तो तुरंत उनका टैस्ट होना चाहिए। उस लड़की का दो दिन के बाद टैस्ट हुआ और आरोपियों को आज दिन तक पकड़ा नहीं गया। पुलिस ने भी आना-कानी की और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भी इसमें मिला हुआ है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसके बारे में जांच की जाए ताकि उस परिवार व लड़की को न्याय मिल सके।

27-02-2024/1205एन0एस0-ए0एस0/3

अध्यक्ष महोदय, प्राइमरी हैल्थ सेंटर, लुहारा में हैं और मैंने कई बार इसके बारे में चर्चा की है लेकिन ये हैल्थ सेंटर पंचायत भवन में चल रहा है और वहां पर इतना कंजस्टिड एरिया है कि वहां पर न तो डॉक्टर बैठ सकता है और न ही फार्मासिस्ट बैठ सकता है जबकि पिछली सरकार के समय में इस पी0एच0सी0 के लिए जमीन उपलब्ध है

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

27.02.2024/1210/RKS/डीसी-1

श्री इन्द्र सिंह.... जारी

इसके लिए वहां धन का भी प्रावधान है लेकिन फिर भी उस भवन का निर्माण नहीं किया जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि उस भवन का निर्माण न होने के क्या कारण हैं? यह संस्थान 3-4 पंचायतों को सर्व करता है और हर रोज वहां लगभग दो सौ ओ.पी.डी. होती है। इस पी.एच.सी. में एक डॉक्टर बैठता है। वहां पर कोई भी स्टॉफ नर्स, फीमेल हैल्थ वर्कर और मेल हैल्थ वर्कर नियुक्त नहीं हैं। यह संस्थान धक्केशाही से चला हुआ है। मेरा आग्रह है कि प्राइमरी हैल्थ सैंटर, लौहारा में पूरा स्टाफ नियुक्त किया जाए और इसके भवन निर्माण का कार्य भी शीघ्र शुरू किया जाए। इसके लिए जमीन और राशि का प्रावधान कर लिया गया है। अगर यह भवन बन जाता है तो वहां के लोगों को काफी सुविधा होगी। राजगढ़, हैल्थ सब सेंटर को अपग्रेड करके पी.एच.सी. बनाया गया। वहां पर एक ही डॉक्टर अपनी सेवा दे रहा है। उस डॉक्टर के अलावा वहां पर और कोई स्टाफ नहीं है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि आप पी.एच.सी., राजगढ़ में पूरी सुविधा प्रदान करें। इसके अतिरिक्त

पी.एच.सी., गागल को अपग्रेड करके सी.एच.सी. बनाया गया है। इस संस्थान के भवन की हालत भी काफी जर्जर है। मैंने इसकी मरम्मत के लिए कई बार माननीय मंत्री और डायरेक्टर हैल्थ को लिखित में दिया है। इस संस्थान का एक और पोर्शन है उसकी मरम्मत करवाने की भी आवश्यकता है। वहां पर डॉक्टर और फार्मासिस्ट एक ही कमरे में बैठते हैं। डॉक्टर की एक प्राइवेसी होती है लेकिन वहां पर डॉक्टर और फार्मासिस्ट्स इकट्ठे बैठ रहे हैं। वहां पर स्टाफ नर्सिज भी बैठी होती है। वहां पर 7 बीघा भूमि स्वास्थ्य विभाग के नाम चिन्हित है परंतु वर्तमान में वह भूमि केवल 2 बीघा से भी कम रह गई है। मेरा आग्रह है कि उस भूमि की निशानदेही करवाई जाए ताकि यह सारी भूमि स्वास्थ्य विभाग के कब्जे में आ जाए और फिर वहां पर एक अच्छा भवन स्थापित हो सके। उस सी.एच.सी. में एक ही डॉक्टर है। वहां पर एक डेंटल डॉक्टर भी है। मेरा आग्रह है कि इस सी.एच.सी. की कुल स्ट्रेंथ को पूर्ण किया जाए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की 12 पंचायतें इस सी.एच.सी. को सर्व करती हैं। वहां पर पूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस सी.एच.सी. के साथ एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भी है। उस आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी को खांदला पंचायत में स्थापित किया जाए ताकि उन लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। क्योंकि उन लोगों को अपना उपचार करवाने के लिए गागल आना पड़ता है।

27.02.2024/1210/RKS/डीसी-2

लोग चाहते हैं कि सी.एच.सी., गागल में एक प्रयोगशाला स्थापित हो। वहां पर प्रयोगशाला का कोई प्रावधान नहीं है। लोगों को अपने टैस्ट करवाने के लिए मेडिकल कॉलेज, नेरचौक, मण्डी या रत्ती जाना पड़ता है।

**(श्री नन्द लाल, सभापति पदासीन हुए)**

मैं चाहूंगा कि आप इस सुविधा को पूर्ण करने के लिस प्रयास करें। मैंने मंत्री जी को कई बार बल्ह विधान सभा क्षेत्र में आने का निमंत्रण दिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज में जो रोगी कल्याण समिति की बैठक होती है वह 14 महीने से नहीं हो पा रही है। उस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्ज नहीं है। वहां लोगों को अपना उपचार करवाने के लिए एडमिशन हेतु 2-2 घंटे लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। वहां पर ट्रॉमा सेंटर का बुरा हाल है।

वहां पर न के बराबर टैस्ट हो रहे हैं। लोगों को अपना टैस्ट करवाने के लिए बाहर की लैब में जाना पड़ता है। जब कृष्णा लैब ने वाकआउट किया तो वहां पर फिर दो दिन तक कोई टैस्ट नहीं हुए जिस कारण लोगों को टैस्ट हेतु दर-दर भटकना पड़ा। किसी को रत्ती जाना पड़ा और किसी को दूर लैब में जाना पड़ा। गरीब लोगों के पास पैसा नहीं होता है इसलिए वे अपना टैस्ट करवाने के प्राइवेट लैब में क्यों जाएं? मेरा आग्रह है कि जो वहां लैब है उसे पूर्ण रूप से ठीक करें ताकि वहां लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। उस मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग का डॉक्टर नहीं है। वहां पर डॉक्टर्ज के बहुत से पद खाली पड़े हैा। उस मेडिकल कॉलेज में जो अच्छे डॉक्टर्ज थे उन्हें वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है।

श्री बी.एस.द्वारा जारी

27.02.2024/1215/बी.एस./डी सी/-1

श्री इन्द्र सिंह जारी...

उन्हें रोहड़ू, रामपुर और ऊना भेज दिया गया है। हमारे वहां बदले की भावना से डॉक्टरों को बदला गया है। मैं चाहता हूं कि छह नहीं तो चार अच्छे डॉक्टर्ज वहां पर होने चाहिए ताकि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। मंत्री महोदय, जो मेरा सिविल अस्पतल, रिवालसर बना है, सिविल अस्पताल में कितने डॉक्टर्ज होने चाहिए? वहां पर केवल तीन ही डॉक्टर्ज सेवाएं दे रहे हैं। उनके सहारे वह सिविल अस्पताल चल रहा है। वहां पर न कोई सेवादार है और नहीं ही कोई सफाई कर्मचारी है। आपकी सरकार में सारी जगह ऐसी ही व्यवस्था बनी है। यह किस चीज का व्यवस्था परिवर्तन है? आप बातें करते है कि प्रदेश में सभी का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए परंतु अस्पतालों में डॉक्टर्ज नहीं होंगे तो यह कैसे संभव है? मेरे सिविल अस्पताल की जो बिल्डिंग बन रही है उसकी खिड़कियां और दरवाजे सड़ रहे हैं, आप लोगों ने पैसा रोक दिया है। इस भवन का निर्माण कैसे होगा और लोगों को कैसे अच्छी सुविधाएं मिलेंगी? मेरा आपसे निवेदन है कि वहां उस ठेकेदार की पेमेंट रोग दी गई है और वह वहां पर काम नहीं कर रहा है। रिवालसर 25 पंचायतों का हब है, आपकी कोठीगिरी से ले करके लेदा के लोग वहां पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। इसलिए वहां पर जितने डॉक्टर्ज की पोस्टे स्वीकृत हैं उन्हें भरने की कृपा करें। हमारे लेदा में एक पी.एच.सी. खाली है, मैं आदरणीय जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं,

वह पी.एच.सी. बहुत अच्छी चली है परंतु वहां भी एक ही डॉक्टर के सहारे यह चली हुई है। मैं चाहता हूं कि जितनी भी पी.एच.सीज. खुली हैं, चाहे वे सत्ता पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोक हैं सभी जगह स्टाफ नर्सिज का पद होना चाहिए, ताकि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सकें। मेरी पी.एच.सी.,लेदा में त्रासदी के समय का डंगा गिरा हुआ है उसमें दरारें आ चुकी हैं। उस बारे में डाक्टर का प्रस्ताव भी आ चुका है। लोग और डॉक्टर वहां पर डर रहे हैं, वहां पर इस पी.एच.सी. के लिए खतरा बना हुआ है। कृपया इस डंगे को जल्द लगाने के आदेश करें। भड़याल ए.सी.एच.सी. की बात करूं तो यह जर्जर हो चुकी है और गिरने की कागार पर है। मेरा कहने का मतलब है कि उस जर्जर स्वास्थ्य केन्द्र को ठीक करने की कृपा करें ताकि लोगों को वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, अन्यथा वहां लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद और मैंने जो स्वास्थ्य संबंधी बातें यहां पर रखी हैं, मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इन पर अवश्य गौर किया जाए, केवल लिखा ही नहीं जाए, धन्यवाद।

27.02.2024/1215/बी.एस./डी सी/-2

**सभापति :** अब माननीय सदस्य दीप राज जी चर्चा में भाग लेंगे।

**श्री दीप राज :** उपस्थित नहीं।

**सभापति :** अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री :** सभापति महोदय, मैं मांग संख्याः 9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कटौती प्रस्ताव की चर्चा का उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं। 17 Members spoke on this Demand.

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

27.02.2024/1220/डीटी/एचके-1

स्वास्थ्य मंत्री जारी...

सभापति महोदय, इस चर्चा का आरंभ माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी ने किया और बड़ी विस्तृत रूप से बहुत अच्छे सुझाव इन्होंने दिए। मैं बीच-बीच में जहां-जहां भी आवश्यक होगा उनको उद्धृत भी करता रहूंगा।

**(माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए)**

Second Hon'ble Member was Shri Satpal Singh Sattiji and third was Hon'ble Shir Sukh Ram Chaudhariji and forth Hon'ble Member was Shri Anil Sharmaji. The fifth speaker was Hon'ble Dr. Hans Rajji, who remained Deputy Speaker of this august House. The sixth one was Hon'ble Dr. Janak Rajji, who is very learned personality in the field of Medical and had given valuable suggestions वास्तव में सभी माननीय सदस्ययों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए। विपक्ष से हमारे सातवें वक्ता थे माननीय श्री रणधीर शर्मा जी and he gave a very detail amount of various suggestions. The Eight Speaker was Hon'ble Member Shri Vinod Kumarji, who had also given very important suggestions. Then in the ninth number was Hon'ble Member Shri Dalip Thakurji after him the next speaker who was in number 10 was Hon'ble Member Shri Trilok Jamwalji after that we had Hon'ble Speaker Shri Puran Chand Thakurji and the twelfth was Smt. Reena Kashyapji, she also gave good suggestions and then Shri Rakesh Jamwalji and after that we had Hon'ble Member Shri Jeet Ram Katwalji. The fifteenth speaker was Shri Pawan Kajalji, and the sixteenth Hon'ble Member was Shri D.S. Thakurji and last speaker was Shri Inder Singh Gandhiji जिन्होंने अभी-अभी सदन के समक्ष अच्छे सुझाव दिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही उपयोगी और अच्छे सुझाव दिए गए and it was a very detailed discussion. I didn't count the whole time but I think it was written by the Table Officers here. ऐसी विस्तृत चर्चा होने से जो

कमियां हैं वह भी सामने आती हैं। किस प्रकार से हम विभाग को सुचारूरूप से चलाएं और जहां सुविधाओं में कमी हैं उनमें कैसे सुधार हो। सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं It's not only a single operation of a leader or an organization but I am of the view जो स्वास्थ्य जैसी चर्चा है और जिस प्रकार से वह इस माननीय सदन में हुई, मैं इस चर्चा का स्वागत करता हूं, I also appreciate it. It's a joint responsibility of each one of us that the people of the State get due health care and health care must be of our priority. मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूं। आजकल मैडम स्टोक्स अस्वस्थ्य हैं, she is a very senior leader. I remember when I got an opportunity to see her outside the State, since she knew all the doctors who were posted in that hospital one or two of them were of our State. वे डाक्टर हमें चाय पिलाने ले गए और एक-डेढ़ घंटा हमारी उनसे बातचीत हुई। डाक्टरों ने उनसे पूछा कि आप कहां बैठे और उन्होंने कहा कि आप एक कैंसर अस्पताल में बैठे हो। हमें इसके बारे में सूचना तक ही नहीं और अंदाजा भी नहीं था कि we were sitting and chatting for such a long time.

श्री एन.जी.द्वारा जारी

**27-02-2024/1225/एच.के.-एन.जी/1**

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री.....जारी**

वहां पर इतनी स्वच्छता है और वहां का माहौल इतना अच्छा है कि I still remember when I recall it and I wish one day our health institutions are on the same line. वे इतने स्वच्छ हों जैसे हमारे मंदिर व अन्य पूजा-अर्चना के स्थान होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि यदि स्वस्थ व स्वच्छ शरीर हो तो हमारा मन भी शक्तिशाली होता है और उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। इस माननीय सदन में उन्होंने श्री विक्रम बत्रा जी के संदर्भ में उद्रित किया था। उन्होंने

कहा था कि श्री विक्रम बत्रा जी का निर्णय मजबूत मन से लिया गया था और मन तब मजबूत बनता है जब शरीर स्वस्थ, मजबूत व पवित्र हो। हम ऐसे स्वास्थ्य संस्थानों की परिकल्पना करें जहां पर एक आदमी केवल स्वस्थ होकर ही बाहर न आए बल्कि ऊर्जापूर्ण व सक्षम हो कर बाहर आए। उसके मन में यह भावना हो कि मैं जितना स्वस्थ हुआ हूं उससे अच्छा काम अपने लोगों के लिए करूं। That should be the aim.

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा है कि इस चर्चा में हमारे 17 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। उन सब के मैंने अलग-अलग नाम इसलिए लिए क्योंकि उन सब ने among their speeches 4 to 5 items were common. जिनके बारे में मैं आपको बाद में बताना चाहूंगा। But otherwise each one had some good suggestions that is how to improve our functioning. अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री इस विभाग के साथ बहुत नजदीक से जुड़ रहते हैं। वे डी.एम.ई. का कार्यभार स्वयं देखते हैं। उनके होने से मुझे तो संबल ही मिलता है और उनके मार्गदर्शन में हम इस विभाग के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर माननीय सदस्यों ने अपने अलग-अलग सुझाव भी दिए हैं। मैं माननीय सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है।

**27-02-2024/1225/एच.के.-एन.जी/2**

इसी कड़ी में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सरकार एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने जा रही है। इसके लिए यहां पर बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं और उनका जिक्र मैं बाद में करूंगा। Certainly we shall have a separate cadre for our specialists and a separate cadre for our general medical officers, परंतु अभी हमने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की परिकल्पना की है। After all why are we thinking of it. यह इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 75 to 80 per cent of population live in rural areas और ग्रमीण लोगों को वे सुविधाएं मिलें जो हमें पी.जी.आई. व बिलासपुर के एम्ज़ में मिलती हैं। हिमाचल का हर व्यक्ति बिलासपुर या पी.जी.आई. नहीं जा सकता। सिरमौर के

शिलाई व शिमला के चौपाल और कुपवी का मरीज बिलासपुर नहीं पहुंच पाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों का स्थापित करने का प्लान बनाया है और लगभग 35 संस्थान यदि मैं गलत नहीं हूं तो हमारे 2- 3 विशेषज्ञ चले भी गए हैं।। was going through the list in the morning, इनमें 6 प्रकार के विशेषज्ञों को रखने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इनमें 134 प्रकार के लैब टैस्ट, एक्स-रे, अल्ट्रासोनोग्राफी के साथ-साथ चिन्हित स्वास्थ्य संस्थानों में सीटी स्कैन व एम.आर.आई. की सुविधा भी उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। जिससे प्रदेश की जनता को ये सुविधाएं घर-द्वार के नजदीक ही उपलब्ध हो जाएं एवं उन्हें छोटी-छोटी समस्याओं के लिए भी मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पतालों में न जाना पड़े। The underlined idea is that

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

**27.02.2024/1230/केएस/वाईके/1**

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी**---

हम ग्रामीण परिवेश में वे सभी सुविधाएं दे सकें जो हम आई.जी.एम.सी., के.एन.एच. या डी.डी.यू., टांडा मैडिकल कॉलेज या दूसरे सिविल अस्पतालों में उम्मीद रखते हैं तथा आपको वहां ना जाना पड़े। अगर आपके पास 4 से 6 स्पैशिलिस्ट हों, अमूमन हम जब गांव में जाते हैं, मैं जहां भी जाता हूं मुझसे यही पूछा जाता है कि आप यहां पर सुन्न करने वाली मशीन कब दे रहे हैं? मैं आपको बता दूं वैसे इसका विवरण बाद में भी आएगा, we just passing reference that I myself the Chairman of this Medical Corporation. ...(Interruption)

**अध्यक्ष :** आज मंत्री जी आप सभी की तसल्ली करवाएंगे। He will take nearly one hour today. अभी तो ये शुरू ही हुए हैं। अभी तो भूमिका ही बना रहे हैं। मंत्री जी, आप खुल कर बोल सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है।

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री :** अध्यक्ष जी, मैंने सभी माननीय सदस्यों के प्वाइंट नोट किए हैं। मैं वैसे ही नहीं लिख रहा था।

Hon'ble Speaker, Sir, thank you. But I must say that you are running this august House so well. You have improved the dress code of two Hon'ble Members, I was really personally must compliment you for that. That is the fact that if you not be dressed up properly विशेष रूप से जो हमारे पूर्व उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस संवैधानिक कुर्सी को सुशोभित किया है, बताया गया something you have improved which is a matter of honour for this august House. मैं स्वास्थ्य संस्थानों की बात कर रहा था। इनमें 4 से 6 विशेषज्ञ भी इसी आशय से लगाए गए हैं कि अगर वहां पर एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर नहीं होगा तो how will the surgeon operate. हम यह भी देख रहे हैं कि जिन-जिन के पास पुराने वक्त के बने हुए संस्थान हैं, चाहे लाहौल-स्पिति का हो, हमीरपुर या बिलासपुर का हो, बहुत सी जगह पर पुराने संस्थान बने हुए हैं। Even some time PHCs are there, PHCs should be remained there and they should not be demolished. उसको इम्प्रूव करके, उसको और एक्सपेंड करके विशेषज्ञ के लिए जगह बनाएं। मैं तो यह भी कहता रहता हूं कि we shall create merit accommodation at least for 50 per cent of the population of doctors or paramedics यह सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जब

**27.02.2024/1230/केएस/वाईके/2**

तक अच्छी सुविधाएं नहीं होंगी, उनके रहन-सहन का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो वहां पर डॉक्टर नहीं आएंगे। बहुत से स्थानों पर when I was Member of Parliament I used to see पहली डिमांड यही होती थी कि यहां पर रहने का कमरा बनवाओ। उपाध्यक्ष श्री विनय कुमार जी के क्षेत्र में एक-दो जगह रहने का इंतज़ाम करना पड़ा तब वहां पर डॉक्टर रहने लगे। अतः सुविधाएं देना बहुत ज़रूरी है। अभी कोशिश की जा रही है कि विभिन्न स्पैशेलिस्टों को एक टीम के रूप में नियुक्त किया जाए। अगर वहां पर पूरी टीम होगी तो अच्छा काम होगा और अगर टीम में कोई कमी रहेगी तो काम में भी विघ्न पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, चिन्हित स्वास्थ्य संस्थानों में हम सीटी स्कैन और एम.आर.आई की सुविधा उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया आरम्भ कर रहे हैं। क्योंकि अगर वे ही चीजें धीरे-धीरे, और हम चाहते भी यही है कि a sort of Mini Civil Hospital and Mini Zonal Hospital facilities must be transported to the rural areas इसके पीछे उद्देश्य यही है। स्वास्थ्य

संस्थानों में उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए इस बजट में 1 करोड़ रुपये प्रति स्वास्थ्य संस्थान देने का प्रस्ताव भी रखा गया है और जो उससे पूरा नहीं हो सकेगा उसको हम अडिशनल फंड भी देंगे। मैं सदन एवं माननीय सदस्यों के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि विभाग ने पैरा मैडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। माननीय सदस्यों ने हैल्थ सब सैंटर्ज़ में सी.एच.ओ. के पद भरने की बात की है, उसके बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि सी.एच.ओ. के 530 पद, स्टाफ नर्स के 622 पद,

**श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी** ---

**27.02.2024/1235/av/yk/1**

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री**--------- **जारी**

ओ0टी0ए0 के 136 पद, काउंसलर के 57 पद और लगभग 25 विभिन्न श्रेणियों के दूसरे पद हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से भरे जा रहे हैं। इससे विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी की समस्या दूर हो जाएगी। सामान्य तौर पर हम सोचते हैं कि हमारे पास ओ0टी0ए0 या रेडियोग्राफर की कमी है, मैं इसके आंकड़े आपको बाद मैं दूंगा। I think it is 34, if I am not wrong. इस प्रकार की ट्रेनिंग जी0डी0एम0ओ0 को दी जा रही है। They must impart such sort of ultrasound training ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न हो क्योंकि यह कमी बहुत रहती है और मैं आपको इसकी बैकग्राउंड दे दूंगा। Why OTA is missing, I myself found it very difficult for a year back. I found the same problem everywhere. Wherever I visited, whether it was in District Kullu, Chamba or anywhere, OTA are missing in that respective areas. फिर हमने इस बारे में सोचा क्योंकि ओ0टी0ए0 को प्राइवेट संस्थानों में या in abroad, they get better remuneration. मान लो अगर हम उनको 20,000 रुपये की राशि दे रहे हैं तो वहां उनको 1.20 लाख रुपये मिल रहे हैं। इसलिए वे प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। हमने फिर इसके निराकरण हेतु यह सोचा कि अपने

जी0डी0एम0ओ0 को 6-6 महीने की अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग दी जाए। Only about after a week, you will have this sort of facility in your various institutions particular in your PHCs or in Adarsh Health Institutions. आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जोकि आपने चिन्हित करने हैं क्योंकि as an MLA you know the topography of your Constituency. You know about the population of villages falls in your Constituency. उनके विधान सभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति कैसी है। वहां से कौन से केंद्र बिन्दु से हमारी ज्यादा-से-ज्यादा पंचायतों को लाभ मिल सकता है। Why I am saying so, because I want to tell you that as an Army officer we are told to always be trained in double trade. Double trade means आपको फायर करना तो आता ही है परंतु आपको ड्राइविंग सीखना भी जरूरी है। So an Officer has to be perforced as a good driver

**27.02.2024/1235/av/yk/2**

also. Why because any time bombshell come and he gets kill there in the battle. So it is necessary that an officer can operate a RCL gun. अगर इस प्रकार की कैजुअल्टी हो जाती है तो ऑफिसर को अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके ले जानी होती है। Therefore, double trade system in any occasion, in any office or in any organization is recommended and that's what we are doing and these 24 people will come to you and after sometime another batch of similar number of official will be trained. तो आपकी वह समस्या हल हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें से आई0जी0एम0सी0 शिमला एवं डॉ0आर0पी0जी0एम0सी0 टाण्डा में पर्याप्त संख्या में कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर उपलब्ध हैं। विभाग में स्पेशलिस्ट्स कॉडर को अलग कॉडर बनाने की प्रक्रिया भी एडवांस्ड स्टेज पर है। यहां पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री विपिन सिंह परमार जी ने एक बात कही थी he said that it is a very important and even Dr. Janak Raj told me इसलिए यह प्रक्रिया एडवांस्ड स्टेज पर है और उनके आर0 एण्ड पी0 रूल्ज बनाए जा रहे हैं तथा प्रदेश में हम इसको शीघ्र ही कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखते हैं। मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि हिम केयर,

सहारा और आयुष्मान भारत योजनाओं का लाभ प्रदेश के पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारी सरकार ने माह दिसम्बर, 2022 से अब तक लगभग 67 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। सहारा योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करवा रहे हैं उनकी अदायगी साथ-साथ सुनिश्चित की जा रही है।। know there was a problem और इनकी लायबिलिटीज के बारे में प्रश्न भी आया था जिस पर काफी डिटेल में चर्चा हुई थी।। can assure you that, may be in a week or two, there will no liability left as we will be having adequate funds to clear those liabilities.

**टी सी द्वारा जारी**

**27.02.2024/1240/टी0सी0वी0/वाई0के0-1**
**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ... जारी**

लायबिलिटी होना किसी भी संस्था के काम की एफिशिएंसी पर असर डालता है। हम समझ सकते हैं कि अगर किसी बेसहारा को जरूरत होती है और उसका कार्ड न चले तो यह उसके लिए असुविधा ही नहीं बल्कि एक प्रकार से बहुत बड़ी पीड़ा भी है। मैं इस माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि **there will be no liability and we shall have all these three schemes including SAHARA going on properly.** अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिनके नाम मैंने शुरू में लिए हैं। इन माननीय सदस्यों द्वारा एक बहुत ही गम्भीर समस्या को उठाया गया है जोकि स्वास्थ्य संस्थानों में दवाइयों की उपलब्धता और इससे जुड़े माफिया के बारे में है। इससे संबंधित आज प्रश्न भी लगा था। इस बारे में पूर्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और दूसरे सदस्यों ने भी चिंता जाहिर की है। I fully appreciate the sentiments that we must be able to give due and proper medicines, particularly, to the poorer sections of the society which comprises a lot, particularly, in the rural areas. उन लोगों को अगर हम दवाइयां ठीक प्रकार से नहीं दे सकें या उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वे न मिल पाएं तो यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बड़ी गम्भीर समस्या है। Probably those who are in such nefarious activities, they want to get overnight rich. I don't know what is the aim

behind it. लेकिन यह हमारे देश भारत या प्रदेश का मसला ही नहीं है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। मुझे तो यहां तक भी पता चला है कि ये ऐसे गिरोह हैं जो किसी भी जगह से ऑपरेट कर सकते हैं। I will give you an instance. When I was Member of Parliament, I was Member of Narcotics Board of India. Shri Oscar Fernandes was the Chairperson. I asked him this question. यह मुसीबत कहां से पैदा होती है? Who are the people who sow the seeds of this very dangerous plant? He says that let me tell you very frankly. Whatever research I could do, I found they are very far-off places which you cannot even imagine in what quantity they are doing it. They are doing it in an international gang operating on it. Then they are sending it to various countries. Our country is a poorer squad. Whosoever forces you may employ, there will be gaps. So this porous powder is another problem. Area adjacent to the international boundaries is another problem and those people are supported sometime unfortunately. I am seeing in this august



House and some people who met, no nobody is going to give a certificate that I have told him that you please bring this much so that I become overnight millionaire, but he says there are groups unfortunately which are operating और उनका संरक्षण उन्हें प्राप्त होता है। अगर इस प्रकार की चीजें होंगी तो हमारी कल की जनरेशन का क्या होगा? The children who are sitting and watching these proceedings today, what will they become if they become a drug addict. That is exactly what I am trying to inform this august House. Once again I wish to express my concern on this.

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि हमारी सरकार बहुत से रिफॉर्म जैसे मैंने कहा कि 'मेडिकल सर्विसीज कारपोरेशन' का गठन किया गया है। मैं स्वयं इसका चेयरमैन हूं। हर विधान सभा चुनाव क्षेत्र में एक आर्दश स्वास्थ्य संस्थान खोला जाएगा जिसकी स्थापना मेडिकल कॉलेजिज में की जाएगी और आधुनिक तकनीक से लैस विभिन्न उपकरणों जैसे रोबोटिक सर्जरी, पैट स्कैन, न्यूनतम एम0आर0आई0

मशीन इत्यादि पर पहले से ही काम आरम्भ कर दिया गया है। **I am sure we shall be able to complete this mission. I** had a personal discussion with Hon'ble Shri Mandaviyaji. I must say, he is a very sensitive personality to all these things. Not that he will personally oblige me, but as a matter of his personality, he said, I will certainly look into your problem wherever you want and whenever you want, you can come. So I want second time.

एन0एस0 द्वारा .. जारी

27-02-2024/1245/एन0एस0-ए0जी0/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री -------जारी

मुझे अभी तक याद है कि उसमें 73 देश बाहर के भी आए थे और सभी लोगों ने प्रशंसा की कि Indian Doctors are the best. जो लोग अफगानिस्तान से आए या अन्य प्रदेशों से आई माताएं-बहनें बता रही थीं और भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे थे। No doubt, medical system of our country is much better. जो भी डिसाइड करने के नॉर्म्ज होते हैं तो मैं कई बार आंकड़े देखता रहता हूं। Overall medically our country is doing very-well. तो क्यों न हमारे बच्चे in the field of robotic surgery, PET scan and MRI, they should go down upto these Adarsh Swasthya Sansthans one day. मैं यही परिकल्पना करना चाहता हूं। इसी के साथ विभिन्न सदस्यों द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों पर **I promise that I will preserve these chits. There may not be time to read out each and everything, but some of them …**

**Speaker:** You can read. There is lot of time. …(Interruption) Minister can take his time. इतनी बड़ी डिस्कशन हुई, he should reply properly to the discussion. यह थोड़ी है। मंत्री जी, आप अपना उत्तर पूरा कीजिए। आप इनकी पूरी तसल्ली करवाएं।

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री :** इसके बाद बहुत संवेदनशील सब्जैक्ट आया। I think it had come from only lone lady Member, Smt. Reena Kashyapji. गर्भवती महिलाओं को फ्री अल्ट्रा साउंड की सुविधा मिले और यह कब मिले जब इनके द्वारा चिन्हित हों। अब मुख्य मंत्री जी सदन में आ गए हैं, he has a personal experience of

robotic surgery. He will also interject and intervene. रोबोटिक सर्जरी का इन्हें पर्सनल ज्ञान है और बड़ा अच्छा अपडेटिड नॉलेज इनके पास है। No wonder, हमें एक दिन उन सुविधाओं की परिकल्पना करनी चाहिए कि धीरे-धीरे जो सुविधाएं हमें चमियाणा, आई0जी0एम0सी0, के0एन0एच0, डी0डी0यू0 या मेडिकल कॉलेज, टांडा या धर्मशाला में मिलती हैं तो वे सब सुविधाएं एक दिन हमारे उन गांव में जहां मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि धीरे-धीरे करके चरणबद्ध तरीके से 6 विशेषज्ञ डॉक्टरों को वहां पर लगाएंगे। मैं समझता हूं कि जो आपके सुझाव हैं, if the Hon'ble Speaker allows me, I will read out to you कि आप लोगों ने कितने अच्छे सुझाव दिए हैं। गर्भवती महिलाओं का एक केस आया and it came from Lahaul & Spiti area and they had tried to evacuate that lady, but by the time they reached KNH, she was no more.

27-02-2024/1245/एन0एस0-ए0जी0/2

इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हमारे पास एयर फेसिलिटी नहीं होगी और ये सुविधाएं कब होंगी जब हम इसको प्लान करेंगे। For example multi-speciality hospital is coming up in Solan and our existing infrastructure is of a city hospital. जो आ रहा है उस पर स्पेशियली जो टोप पर क्रिटिकल केयर ब्लॉक के ऊपर चौपर को लैंड करने की सुविधा होनी चाहिए। इसको थोड़ा आगे-पीछे कर रहे थे लेकिन मैंने कहा कि इसको फॉर्मली ग्राउंड पर लाओ and particularly, critical care block can also be back there only. और इसके ऊपर हमें चौपर या हेलीकॉप्टर को लैंड करने की सुविधा होनी चाहिए। मेरा सच में एक सपना है कि हम हरेक सिविल होस्पिटल में कम-से-कम if not even lower, we should be able to give this facility, particularly, in our border areas. हमारे बड़े दुर्गम स्थान हैं। उन जगहों में जैसे एक उदाहरण मेरे पास आया कि गर्भवती महिला जिसने अपनी जान गंवा दी, उनको इवैक्यूएट करना तभी संभव होगा जब हम इस प्रकार की सुविधाओं की परिकल्पना करेंगे। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रा साउंड की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए रेडियोलॉजिस्ट इस प्रदेश में बहुत कम स्थानों पर उपलब्ध थे जिसके मद्देनजर अभी 34 चिकित्सा अधिकारियों को अल्ट्रा सोनोग्राफी की ट्रेनिंग दी गई है। वे शीघ्र ही होस्पिटल्ज में आ जाएंगे। इतने ही और चिकित्सा अधिकारियों को यह ट्रेनिंग हम जल्दी ही करवाने जा रहे हैं

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

27.02.2024/1250/RKS/एएस-1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री.... जारी

ताकि गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड घर-द्वार के नजदीक स्वास्थ्य संस्थानों में हो सकें। If medical doctor will be better qualified, if he knows ultrasonography in addition to his general medicine or the MBA training he had ...(व्यवधान) ये आप ही लोगों के दिए हुए प्वाइंट हैं।

**Speaker** : Let him reply please. सैटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि आप इसको विद्ड्रा कर रहे हैं। Then he will sit down. If you are likely to withdraw then obviously he will sit down, otherwise he will make you satisfy. Hon'ble Health Minister please continue with your reply.

**Health Minister** : Mr. Speaker, Sir, regarding Oral Health, यहां डेंटल के बारे में 2-3 बार बात हुई। इन्होंने कहा कि ओरल हैल्थ के बारे में कोई भी चीज इंक्लूड नहीं की गई है। We are happy, our Deputy Chief Minister has come despite all adverse condition that divine forces have done. He has come to this House, we should appreciate his spirit. ओरल हैल्थ के अंतगर्त हमारा मुस्कान प्रोजैक्ट को चलाने का कार्यक्रम है। विभाग ने इसी वर्ष लगभग 20 दंत चिकित्सकों को विभिन्न स्थानों से नियुक्त किया है। इसमें पांच वर्ष बाद बैच वाइज नियुक्ति करने का प्रावधान भी किया गया है। मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत जो बेरोजगार डेंटल डॉक्टर्ज हैं उनको सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि it is a path breaking step और जो हमारे बेरोजगार dental officers who are sitting back without any employment they will get this facility. जिन बच्चों की जन्म से सुनने की क्षमता नहीं होती उनमें Cochlear plants अभी भी लगाए जा रहे हैं। यह प्रश्न बीच में आया था। पिछले वर्ष 5 बच्चों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई हैं। एक Cochlear plants पर सवा पांच लाख रुपये खर्च होते हैं। कोरोना काल के दौरान जो विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पी.एस.ए. प्लांट लगाए गए थे उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयुक्त धन की

उपलब्धता एवं उनमें कार्यरत ओप्रेटर्ज की नियुक्ति पुनः सुनिश्चित कर दी गई है ताकि ये पी.एस.ए. प्लांट कार्यान्वित रहें। यह प्रश्न श्री विनोद कुमार जी का था। मैंने इन्हें बताया

27.02.2024/1250/RKS/एएस-2

कि money has already been given and it has gone to the right quarters and that amount which I had also read yesterday, It was 6,96,300/- and it has gone to from the PWD and it will be provided soon for the repair for the machines. हमारे विभाग व केंद्रीय औषधी मानक नियंत्रण संगठन द्वारा समय-समय पर दवाइयों के सैंपल जांच के उद्देश्य से लिए जाते हैं और रिपोर्ट आने पर गुणवत्ता में कमी पाई जाए तो औषधी एवं प्रसाधन कानून के प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाती है। पूर्व में रहे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं विधान सभा अध्यक्ष ने आज यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था। मैंने इनको बतलाने का प्रयास किया कि मानकों के अनुसार जो दवाइयां 'एम' और 'यू' के नीचे नहीं आती हैं उन्हें हम किस प्रकार डील करते हैं ताकि ये ड्रग्स एब्यूज न हों और जो दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं वे ठीक हों। ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ही दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं बल्कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में भी दवाइयों के सैंपल फेल होते रहे हैं जिनके आंकड़े विभाग के पास मौजूद हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जिस प्रकार औषधी एवं प्रसाधन कानून के अंतर्गत विभाग ने भूतपूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान कार्रवाई अमल में लाई थी, वर्तमान सरकार के समय भी औषधी एवं प्रसाधन कानून के अंतर्गत समय-समय पर यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। The Government is in continuity and continuity will always tight those who are not following the good medical practices they have to face law and some of the issues are also subjudice.

श्री बी.एस.द्वारा जारी

27.02.2024/1255/बी.एस./ए एस/-1

स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी...

हिमाचल प्रदेश में यदि दवाई उत्पादन की मात्रा की बात करें तो यहां पर काफी मात्रा में दवाइयों का उत्पादन होता है। एक प्रश्न में भी था कि 30-35 प्रतिशत हमारे देश में प्रदेश में उत्पाद की गई दवाइयां जाती हैं और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी मात्रा में जा रही हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हमारी गुणवत्ता युक्त दवाइयां होनी चाहिए। इस प्रकार की चीजें न हों कि दवाइयों के सैंपल फेल होते रहें और हम बैठे रहें। आप ने अभी हाल ही में देखा होगा कि हमारे सामने एक घटना आई। वहां पति और पत्नी नकली दवाइयों में संल्पि थे। उनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई गई है। I myself supervise this operation with the Police authorities as well as our drugs authorities. They sent on the ground and the culprits were apprehended and arrested and the case is going on and as per the law, they will suitably punish. विभाग दवाइयों की गुणवत्ता को ले करके वर्तमान निर्देशानुसार गंभीर है और आने वाले समय में भी कानून के प्रावधन के अंतर्गत कार्रवाई की जाती रहेगी। मैं यह भी सदन को बताना चाहूंगा कि दवाइयों के सैंपल की प्रक्रिया को और सुदृढ़ करने के लिए बद्दी में अत्याधुनिक टैस्टिंग लैब स्थापित की गई है और यह 32 करोड़ रुपये से बनी। Soon this Laboratory will be inaugurated by the Hon'ble Chief Minister. माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य संथानों में क्लीनिंग एवं शेनिटेशन का मुद्दा ध्यान में लाया गया है और यह हमारे ध्यान में है। मैं समझता हूं कि it is a very-very important subject and it will be look into and we shall find viable solutions. अध्यक्ष महोदय, हमारे पास हमेशा ही समय की कमी होती है इसलिए जिन माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, मैं उन्हें सुरक्षित रखता हूं और कभी भी माननीय सदस्यों के पास समय होगा हम बैठक करके इस पर अवश्य विचार करेंगे। किसी वक्त भी किसी माननीय सदस्य का सुझाव होगा उसका सम्मान होगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं which I must appreciate once again. अध्यक्ष महोदय, मेरा विपक्ष के सम्माननीय सदस्यों से निवेदन रहेगा कि आपने जो कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं उनको वापिस लेने की कृपा करें।

27.02.2024/1255/बी.एस./ए एस/-2

**अध्यक्ष :** अब जो विपक्ष के माननीय सदस्य हैं जिनके मैं अभी नाम लूंगा, क्या माननीय सदन की अनुमति है कि सर्वश्री विपिन सिंह परमार, सतपाल सिंह सत्ती, सुख राम चौधरी,

बिक्रम सिंह, अनिल शर्मा, डॉ० हंस राज, डॉ० जनक राज, रणधीर शर्मा, विनोद कुमार, दलीप ठाकुर, त्रिलोक जम्वाल, पूर्ण चन्द ठाकुर, लोकेन्दर कुमार, श्रीमती रीना कश्यप, सर्वश्री राकेश जम्वाल, जीत राम कटवाल, पवन कुमार काजल, डी० एस० ठाकुर, इन्द्र सिंह और श्री दीप राज माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव वापिस ले लिए जाएं। Before that I put this to the Vote, I would request all the Hon'ble Members to be on their own seats.

**कटौती प्रस्ताव वापिस हुए।**

अब माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

27.02.2024/1400/डीटी/डीसी-1

**(सदन की बैठक दोपहर के भोजनावकाश के उपरांत 02.00 बजे पुनः आरंभ हुई।)**

**Speaker:** Since there is no Hon'ble Member in the House and the House was adjourned for the lunch break. So it is further being adjourned till the quorum of the House is complete.

**Continued by NG...**

**27-02-2024/1415/एच.के.-एन.जी/1**

**माननीय सदन की बैठक कोरम पूर्ण होने के पश्चात 2:15 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।**

**(विपक्ष के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)**

**<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>**

**अध्यक्ष** : श्री जय राम ठाकुर जी, आप बोलिए। विपक्ष के शेष माननीय सदस्य, कृपया अपनी-अपनी सीट्स पर बैठ जाएं।

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, इस आसन के लिए हमारा बहुत बड़ा सम्मान है। इस माननीय सदन में यदि सत्ता के प्रभाव में कुछ चीज़ें होती हैं तो उन्हें प्रभाव मुक्त करने के

लिए इस आसन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आज बजट प्रस्तुत होने के पश्चात कट मोशन्ज़ पर विपक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से दिए गए महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। व्यवस्था के अनुसार इनमें मतदान होता है। मतदान को लेकर नियमों में स्पष्ट लिखा गया कि यदि वॉयस वोट में क्लीयरिटी नहीं आती है तो विपक्ष को अधिकार है कि वे डीविज़न मांग सकते हैं। आज जब वॉयस वोट के बाद हमारी ओर से डीविज़न मांगने की बात हुई और वॉसय वोट के आधार पर हमारी ताकत ज्यादा थी। ...(व्यवधान) आप लोग सुनिए तो सही। ...(व्यवधान) अब कुछ नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता।...(व्यवधान) आपको श्राप लगेगा। (***)

**अध्यक्ष :** आप तो हमारी नज़र में ही रहते हैं।

**27-02-2024/1415/एच.के.-एन.जी/2**

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, हम सोच रहे थे कि आप इस माननीय सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और पेशे से वकील भी हैं तथा उस दृष्टि से आप हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे। (***)आपकी चेयर के माध्यम से इस रूल बुक में हमें यह अधिकार दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस माननीय सदन में आज की जो परिस्थिति बनी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान सरकार के जिस प्रकार के हालात हमको सामने दिखाई दे रहे हैं उन हालातों के कारण ये अपना मैंडेट खो चुके हैं। आज कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता त्याग पत्र दे रहे हैं और बहुत सारे विधायक अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि हमने यहां पर नियम के मुताबिक ही आपसे डीविज़न वोट के लिए निवेदन किया था और अब तो आपने वह कर दिया, लेकिन आने वाले कल में बजट पास होना है और कल भी तो यह स्थिति आएगी, मेरा आग्रह है कि कल हमें यह अवसर प्रदान किया जाए। (***)

**अध्यक्ष :** माननीय राजस्व मंत्री, आप बोलिए।

राजस्व मंत्री....श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

---

(***) **अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गए।**

**27.02.2024/1420/केएस/एचके/1**

**राजस्व मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, जो मुद्दा माननीय विपक्ष के नेता ने उठाया है, अगर उसको सही परिवेश में देखें तो आपका फैसला बिल्कुल सही था। क्योंकि कट मोशन पर आपने प्रस्ताव को सदन में वोटिंग के लिए डाला। और वाइस वोट से पहले आपने कहा कि सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाएं। जब आपने देखा कि पक्ष और विपक्ष के सारे माननीय सदस्य सीटों पर हैं, इसका मतलब यह हुआ कि सत्ता पक्ष के एक-आध सदस्य को छोड़कर सभी माननीय सदस्य सदन में उपस्थित थे। तो जो नम्बर हमारे पक्ष में था, वह इस वोट में आपने ठीक सैंस किया और आपकी रूलिंग सही थी। तो उसके ऊपर जो माननीय नेता विपक्ष आपत्ति उठा रहे हैं, यह रूल के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। ये बताना चाह रहे हैं कि इनके साथ अन्याय हुआ है और इस किस्म के कोई अन्य ...(व्यवधान) देखो, इनको यही बीमारी लगी हुई है। हम जब बोलते हैं तो ये हमें नहीं बोलने देते। जब ये बोल रहे थे, हमने एक शब्द नहीं कहा।...(व्यवधान)

**Speaker :** Please let the Hon'ble Minister speak.

**राजस्व मंत्री :** अध्यक्ष जी, जब ये बोल रहे थे, हमने एक शब्द भी बीच में नहीं कहा। यह कोई तरीका है? लोकतंत्र कैसे चलेगा? ...(व्यवधान) जब इनको सच्चाई कड़वी लगती है तो ये बीच में आ जाते हैं। सर, आपका निर्णय बिल्कुल सही था। वोट हो गया, वाइस वोट हो गया उसके बाद नेता प्रतिपक्ष उठकर हल्ला करने लग गए जो कि बिल्कुल गलत है, नियमों के खिलाफ़ हैं।

**27.02.2024/1420/केएस/एचके/2**

**श्री विपिन सिंह परमार :** अध्यक्ष महोदय, डिविज़न ऑफ वोट के बारे में हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने बड़े विस्तार में बात रखी। इस चेयर पर मैं भी रूलिंग देता रहा हूं और हम इस चेयर का ऑनर करते हैं और जिस पृष्ठभूमि से आप हैं, हम उसका भी मान-सम्मान करते हैं। परंतु लोकतंत्र में इन चीजों को अगर धक्काशाही से आगे बढ़ाया जाए, शायद लोकतंत्र इसकी इजाज़त नहीं देता। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी को यहां से बार-बार कहा गया कि आप आगे बोलिए, आगे बोलिए, जो मर्जी बोलिए। उसके बाद इसमें प्रावधान

है और नियम है डिविज़न ऑफ वोट का और (***)...(व्यवधान) नेगी जी, आप कौन होते हैं? आप कौन हैं? आप बैठिए। ...(व्यवधान)

(पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो कर नारेबाजी करने लगे)

---

(***) **अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गए।**

**27.02.2024/1420/केएस/एचके/3**

**Speaker :** Whatever acquisitions and insinuations have been made against the Chair by the Member of Opposition, those will be removed from the record. Since, there seems to be disorder in the House, therefore, I adjourn the House and we will reassemble tomorrow at 11:00 AM.

**Shimla-171004** **Yash Paul Sharma**
**Date-27 February, 2024** **Secretary**